

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 19 मार्च, 2009

विषय:-जनपद अल्मोड़ा के तहसील सोमेश्वर के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2422/नौ-52/2001-02 दिनांक 24.01.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रु0 127.58 लाख के विरुद्ध टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु0 125.90 लाख (रु0 एक करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र) के आगणन पर शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करा लिया जाय। योजना का पुनरीक्षण आगणन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए ही पूर्ण की जांच एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्येज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया

जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य का तीसरे पक्ष (स्वतंत्र) से आंकलन कराया जाय।

2. उक्त व्यय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-60-अन्यभवन-आयोजनागत-051-निर्माण-03-तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 198p/XXVII(5)/2008 दिनांक 13.3.09 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या-238 (1)/XVIII(1)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-5
11. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।